

श्रीमती गीता देवी पत्नी श्री शंकर लाल अग्रवाल,
निवासी कुशलबाग पैलेस, बांसवाड़ा

...प्रार्थीया

बनाम

1. कलक्टर (मुद्रांक), वृत्त, उदयपुर
2. राजस्थान सरकार जरिये उपपंजीयक बांसवाड़ा
3. एहमदनूर पुत्र श्री नूरमोहम्मद, निवासी बांसवाड़ा
4. इब्राहीम पुत्र श्री नूरमोहम्मद, निवासी बांसवाड़ा
5. ईस्माईल पुत्र श्री नूरमोहम्मद, निवासी बांसवाड़ा
6. मोहम्मद हुसैन पुत्र श्री नूरमोहम्मद, निवासी बांसवाड़ा

...अप्रार्थीगण

खण्डपीठ

श्री नत्थूराम, सदस्य

श्री के.एल.जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अभिषेक अजमेरा

अभिभाषक

...प्रार्थीया की ओर से

श्री जमील जई

उप-राजकीय अभिभाषक

...अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 की ओर से

श्री हेमराज गुप्ता

रिचा राय

...अप्रार्थी संख्या 4 की ओर से

नाम तर्क किया गया

...अप्रार्थीगण संख्या 3, 5 व 6

निर्णय दिनांक : 11.06.2018

निर्णय

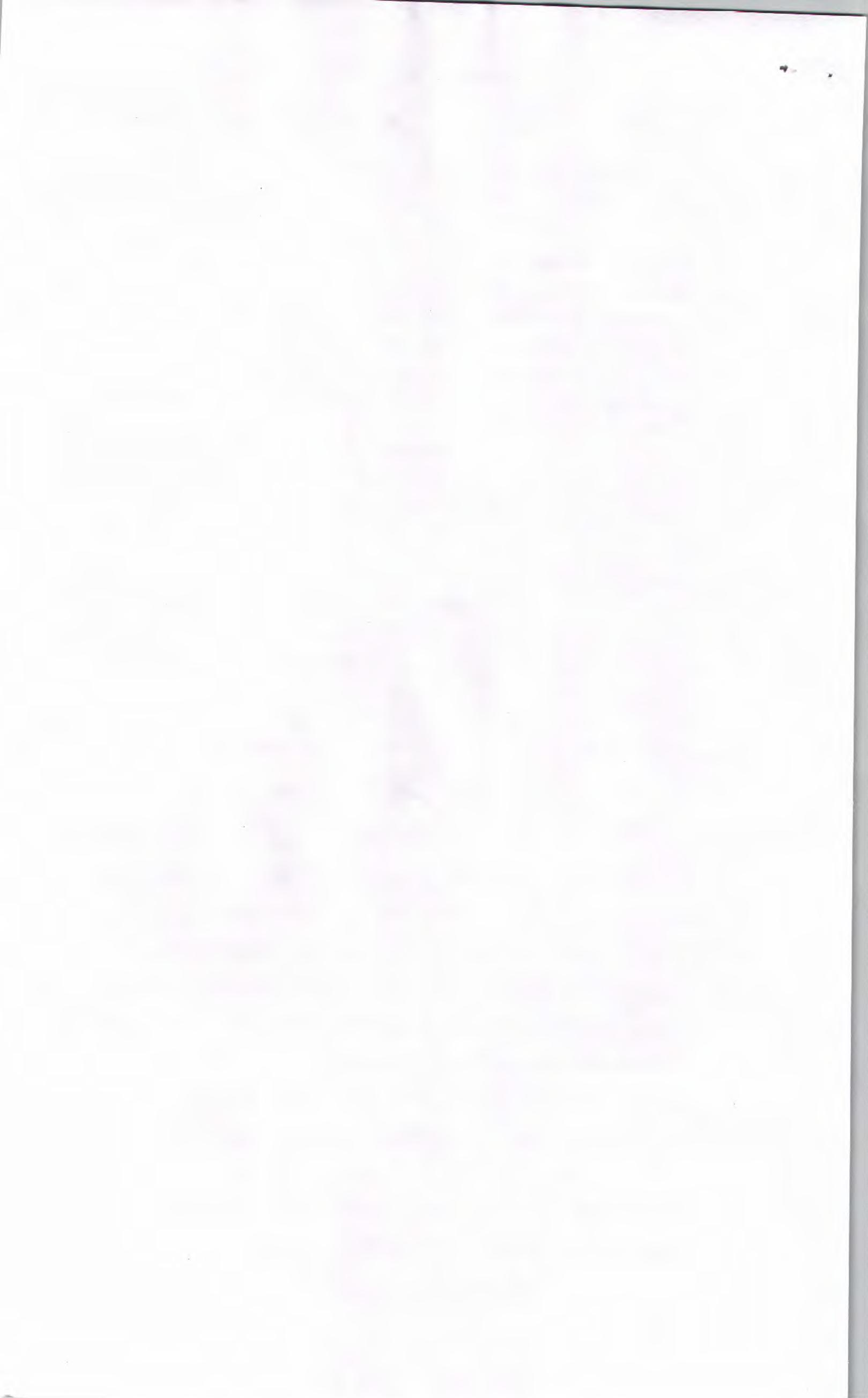
1. यह निगरानी प्रार्थी द्वारा विद्वान कलक्टर (मुद्रांक) वृत्त उदयपुर (जिसे आगे 'कलक्टर' कहा गया है) के आदेश दिनांक 22.02.2012 प्रकरण संख्या 73/2008 एवं आदेश 9 नियम 13 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निर्णय दिनांक 11.08.2014 के विरुद्ध राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 (जिसे आगे 'मुद्रांक अधिनियम' कहा गया है) की धारा 65 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने उपपंजीयक बांसवाड़ा द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स को स्वीकार किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अप्रार्थीगण सं 3 से 6 ने पैतृक संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की जमाबन्दी खाता नं. 79(नई) 383(पुरानी) का सर्वे नम्बर 2515/1188 रकबा 01 बीघा, 13 बिस्वा कृषि भूमि वाके गांव बांसवाड़ा पटवार हल्का बांसवाड़ा तहसील एवं जिला बांसवाड़ा ने प्रार्थीया को 25 लाख रु में कृषि भूमि का सौदा हुआ व उपपंजीयक, बांसवाड़ा के यहाँ दिनांक 03.09.2007 का दस्तावेज





लगातार.....2



पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया जिसे मुद्रांक कर 1,62,500/- व पंजीयन शुल्क 25,000/- रू वसूल कर मूल दस्तावेज संबंधित को लौटा दिये। तत्पश्चात् उपपंजीयक, बांसवाड़ा द्वारा प्रश्नगत दस्तावेज से संबंधित भूमि का मौका निरीक्षण किया गया। मौका निरीक्षण के अनुसार यह पाया गया कि भूमि मुख्य शहर के पास स्थित है तथा चारों तरफ शहर की आबादी फैली हुई है। आवासीय दर से आंकलन कर प्रकरण प्रेषित करना उचित बताया। उक्त आधार पर रेफरेन्स अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिसमें अधीनस्थ न्यायालय में एकपक्षीय कार्यवाही करते हुये निर्णय दिनांक 22.02.2012 द्वारा सम्पत्ति की मालियत 2,01,96,255/- निर्धारित कर कमी मुद्रांक कर राशि रू. 12,37,760/-, कमी पंजीयन शुल्क राशि रू.10,000/- एवं शास्ति राशि रू. 2240/- कुल राशि रू. 12,50,000/- प्रार्थीया से वसूल किये जाने के आदेश दिये गये। प्रार्थीया द्वारा इस एकपक्षीय निर्णय को अपास्त कराने हेतु आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र दिनांक 23.01.2013 को अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जो निर्णय दिनांक 11.08.2014 द्वारा अस्वीकार किया गया। प्रार्थीया द्वारा उपरोक्त निर्णय दिनांक 22.02.2012 एवं 11.08.2014 के विरुद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3. निगरानी दर्ज की जाकर रिकार्ड व अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक एवं अप्रार्थी सं. 4 की ओर से उनके विद्वान अभिभाषक उपस्थित आये। अप्रार्थीगण सं. 3, 5 व 6 का नाम प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर इस आधार पर तर्क किया गया कि मुद्रांक कर का दायित्व प्रार्थीया क्रेता का है।

4. बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई।

5. विद्वान अभिभाषक प्रार्थीया की ओर से कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय नॉन स्पीकिंग है, जिसमें कोई विशिष्ट करण व आधार अंकित ही नहीं किये गये, केवल मात्र नोटिस अन्तर्गत धारा 54 मुद्रांक अधिनियम में लिखा है कि विलेख द्वारा अन्तरित सम्पत्ति का प्रचलित बाजार दर/निरीक्षण द्वारा सही मार्केट के आधार पर कमी मुद्रांक कर जमा करावे। इस प्रकार मुद्रांक कर की कम अदायगी के संबंध में रेफरेन्स संधारणीय व पोषणीय नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि उप पंजीयक के लिखने मात्र से कि भूमि मुख्य शहर के पास हो कर चारों तरफ शहर की आबादी फैली हुई है अतः आवासीय दर से मूल्यांकन किया गया। इस प्रकार उपपंजीयक द्वारा अपने कथनों की पुष्टि में किसी भी प्रकार के कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने एवं बिना दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये अथवा किसी भी प्रकार के बयान प्रस्तुत किये अथवा निगरानीकार को किसी भी प्रकार की कोई साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का अवसर प्रदान किये बिना यह निर्णय आदेश पारित किया है जो



25-

लगातार.....3



विधिसम्मत नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे। इन्होंने अपने समर्थन में माननीय राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर द्वारा निगरानी सं. 602/2016/बांसवाड़ा श्री कौशल अग्रवाल बनाम कलक्टर (मुद्रांक) में पारित निर्णय दिनांक 31.05.2017 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया।

6. विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत है, अतः निगरानी खारिज की जावे।

7. हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :-

8. प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र सशपथ होने, प्रार्थना पत्र में अंकित कारण संतोषजनक एवं विश्वास योग्य होने, निर्णय गुणावगुण के आधार पर श्रेयस्कर होने की दृष्टिगत स्वीकार किया जाकर निगरानी अन्दर मियाद मानी जाती है।

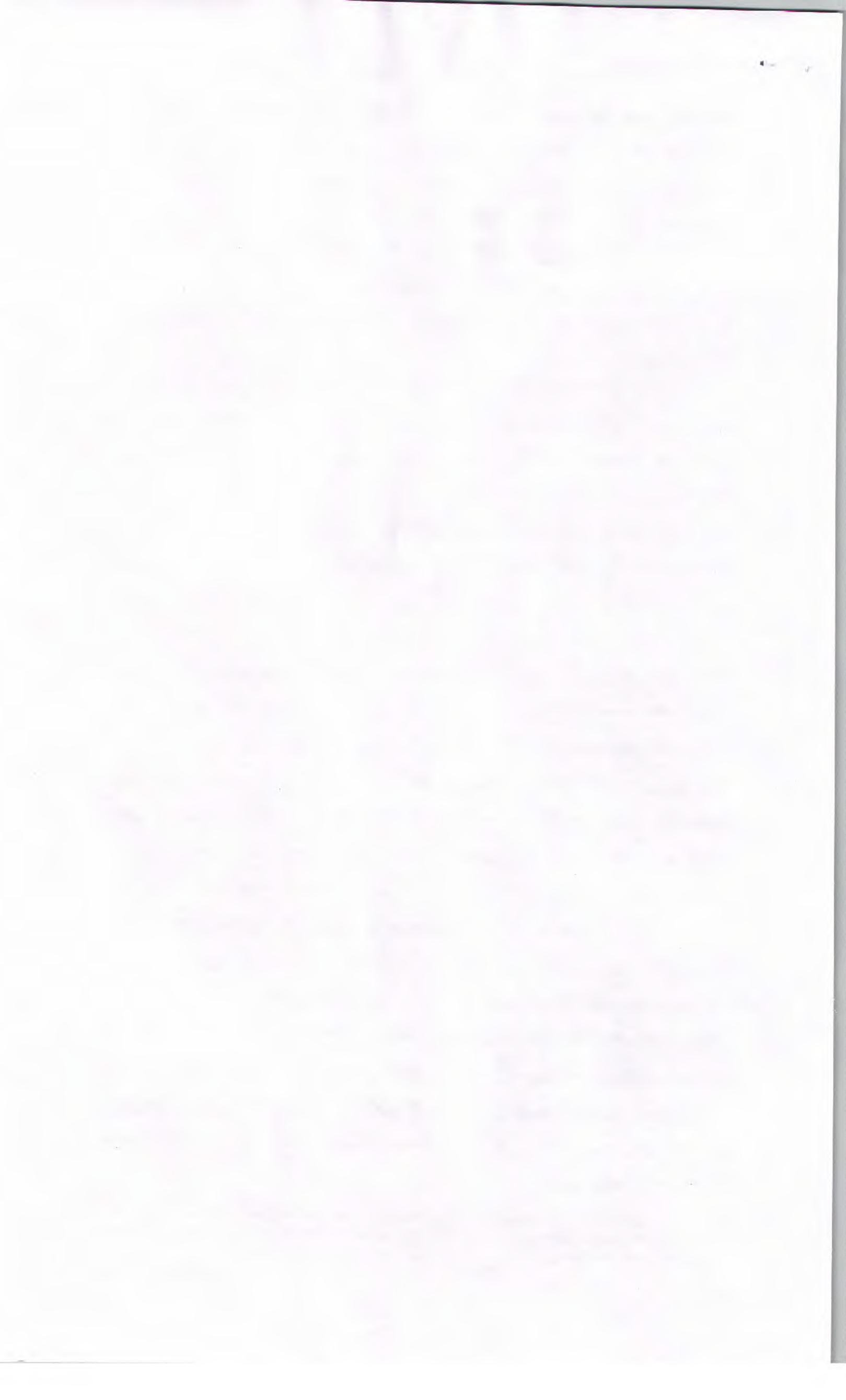
9. निगरानी में मुख्य आधार यह है कि निर्णय में रेफरेन्स के बिन्दुओं को बिना कोई विवेचना एवं विश्लेषण किये पारित किया है जो विधिसम्मत नहीं है। निर्णय साइक्लोस्टाइल है व रिक्त स्थानों में पूर्ति कर निर्णय पारित कर दिया है। निर्णय में तर्क, कारण एवं विधिक विवेचना का अभाव है।

कलक्टर (मुद्रांक) उदयपुर के निगरानीधीन आदेशों के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि कलक्टर (मुद्रांक) ने रेफरेन्स के तथ्यों की विवेचना किये बिना ही रिक्त स्थानों की पूर्ति करके विवादित आदेश पारित किया है, जिसे न्याय संगत आदेश नहीं कहा जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय का दायित्व बनता है कि उसके समक्ष प्रस्तुत प्रकरण में उठाये गये बिन्दुओं की विवेचना करने के उपरान्त ही उन्हें मानने या न मानने पर तथ्यों पर आधारित अपना मत प्रकट करते, जिससे अधीनस्थ न्यायालय के आदेश/निर्णय के विरुद्ध अपील होने पर सम्बन्धित न्यायालय अपना निर्णय पारित करें कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय संगत है अथवा नहीं। किन्तु प्रस्तुत निगरानी में कलक्टर (मुद्रांक) द्वारा ऐसा नहीं किया गया, जिसे उचित नहीं कहा जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय का दायित्व बनता है कि वह सचेतन मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए निष्पक्ष अभिव्यक्ति दें। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय की खण्डपीठ के सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, 'वर्क्स कान्ट्रेक्ट एवं लीजिंग टैक्स, कोटा बनाम मैसर्स शुक्ला एड ब्रदर्स (Civil Appeal No. Nil of 2010/S.L.P.(C)No. 16466 of 2009), date 15.4.2010) में पारित किये गये निर्णय के कुछ अंश उद्धृत किया जाना उक्त परिप्रेक्ष्य में समीचीन होगा :-

"... To subserve the purpose of justice delivery system therefore, it is essential that the Courts should record reasons for its conclusions whether disposing of the case at admission stage or after regular hearing."




लगातार.....4



"A litigant has legitimate expectatoion of knowing reasons for rejection of his claim/payer. It is then alone, that a party would be in a position to challenge the order on appropriate grounds. As arguments bring things hidden and obscure to the light of reasons, reasoned judgment where the law and factual matrix of the case it discussed provided lucidity and foundation for conclusions or exercise of judicial discretation by the Courts. Reason is the very life of law. When the reason of a law once ceases, the law itself generally cease. Such is the signifucance of reasoning in any rule of law. Giving reasons furthers the cause of justice as well as avoids uncertainty. As a matter of fact it helps in the observance of law of precedent . Absence of reasons on the contrary essentially introduces an element of uncertainty, dissatisfaction and give entirely different dimensions to the questions of law raised before the higher appellate Courts. When reasons are announced and can be weighed, the public can have assurance that process of corection is in place and working. It is requirement of law that correction of judgments should not only appeaar to be implemented but also to have been properly implemented. Reasons for an order would ensure and enhance public confidence and would provide duc satisfaction to the consumer of justice under our justice dispensation system." उपरोक्त विधिक धारणा से भी अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत नहीं है।

10. अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि निगरानीधीन निर्णय एकपक्षीय पारित किया गया हैं तथा यदि प्रकरण में निगरानीधीन आदेश निरस्त किया जाकर प्रतिप्रेषित किया जाता है तो न्यायिक दृष्टिकोण से प्रार्थी को सुनवाई का भी समुचित अवसर मिल सकेगा। साथ ही प्रकरण प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत माननीय राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर द्वारा निगरानी सं. 602/2016/बांसवाड़ा श्री कौशल अग्रवाल बनाम कलक्टर (मुद्रांक) में पारित निर्णय दिनांक 31.05.2017 से कवर्ड है जिसमें प्रकरण इसी आधार पर प्रतिप्रेषित किया गया है।

11. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विवेचना-विश्लेषण सहित निर्णय पारित नहीं करने के कारण विधिसम्मत नहीं होने के कारण निगरानी आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निगरानीधीन आदेश निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे उभयपक्ष को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देते हुए, राजस्थान मुद्रांक अधिनियम 2004 के नियम 65 की पालना करते हुए पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए पुनः नियमानुसार एवं विधिसम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 23.07.2018 को पेश हों।

12. निर्णय सुनाया गया।


(क.एल.जैन)
सदस्य


(नत्थूराम)
सदस्य

